

संपादक की कलम से

कैसे करें किसानी

अपनी खेती की जमीन को बचाना है तो प्रयास करना होगा। चुनावी घोषणाओं की गारंटी और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मुगालते में न रहें। किसानों की एकजुटत और बहुफसली प्रणाली ही समस्या का समाधान है। गेहूं और धान के अधिकाधिक उत्पादन से समस्या और विकारल हो जाएगा, इसलिए समय रहते इन फसलों का रकबा कम करते जाएं और अन्य फसलों को रकबा बढ़ाते जाएं। कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण बहुफसली की रकबा बढ़ाती रहती है। अनुसार अभी आगे भी मौसम के तेवर दूर ही सख्त बढ़े रहने की संभावना है। भले ही किसानों को 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) का कानून न मिले, भले ही खरब बहुई फसलों का मुआवजा न मिले, परन्तु किसानों को सरकार और मौसम की मार मिलना तय है। किसानों पर लोहरी मार पड़ने की पंसारा बहुत पुरानी है। एक तो फसलों के सही दाम नहीं मिलते और ऊपर से अब तो लगभग हर साल ही मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ती है। देश में महांगाई का बोलबाला है, परन्तु किसानों की फसलों के दाम वैसे नहीं बढ़ते जैसे सरकारी कर्मचारियों के महांगाई भरत और सेलरी बढ़ती है, जैसे देश के मानवीय सासदों और विधायकों की सैलरी बढ़ती है? अधिकर देश के करोड़ों लोगों को पेट और व्यापियों को वेयर हाऊल भरने वाले किसानों को अपनी उपज का दाम मिलने में इतनी परेशानी क्यों है? क्या कारण है कि सरकार इको 'एमएसपी' भी नहीं दे पा रही है? एक तरफ तो सरकार कह रही है कि किसानों की आमदानी दुगुरी हो गई है, दूसरी तरफ उन्हें 6000 रुपये सालाना 'किसान सम्मान निधि' भी दी जा रही है। जब सरकार को किसानों की निधि ही चिंता है तो पिर 'व्यापारी नान आयों' की रिपोर्ट के अनुसार 'एमएसपी' पर 'सी 2+50 प्रतिशत' फॉम्यूले के नाम से भी जाना जाता है। इस फॉम्यूले में किसानों को 50 प्रतिशत रिटर्न देने के लिए पंजी की अनुमति लागत और भूमि का किराया (जिसे सी-2 कहा जाता है) शामिल है। यदि सरकार चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी को भारतरत्न दें सकती है तो पिर किसानों को उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार 'एमएसपी' क्यों नहीं दे देती? यदि हिंसा से किसानों को अपनी फसल के दाम मिलने लगें तो किसानों को 'किसान सम्मान निधि' की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 'स्वामीनाथन आयोग' को रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को 'एमएसपी' को उत्पादन की औसतत लागत से कम-से-कम 50 प्रतिशत अधिक बढ़ाना चाहिए। इसे 'सी-2+50 प्रतिशत' फॉम्यूले के नाम से भी जाना जाता है। इस फॉम्यूले में किसानों को 50 प्रतिशत रिटर्न देने के लिए पंजी की अनुमति लागत और भूमि का किराया (जिसे सी-2 कहा जाता है) शामिल है। यदि सरकार चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी को भारतरत्न दें सकती है तो पिर किसानों को उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार 'एमएसपी' क्यों नहीं दे सकती? आश्वर्य की बात तो यह है कि चुनाव के समय में भी सरकार की तरफ से कोई नरमी नहीं बढ़ती जा रही। इस बार के चुनावी अंतिम चरण वर्षों एवं किसानों को बड़ी उम्मीदें थीं, जूते रुक्ति की चूंका शाय नहीं लगा। उल्लंघन कृषि बजट में कटौती कर दी गई। प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं रखे गए। प्रश्न उठता है कि देश के किसानों के हालातों में कैसे सुधार आएगा?

एक तरफ किसानों की लागत में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, लागत के अनुपात में फसलों के दाम नहीं मिल रहे, वहीं दूसरी तरफ मौसम के कारण खाली कोंजों ने नुकसान हाता है उसका मुआवजा और बीमा भी समय पर नहीं मिलता। किसानों की परेशानी कम होने का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। किसानों को बीमा तथा मुआवजा समय पर मिलें, इसके लिए भी ठोस कदम उठाना चाहिए। दृष्टिश्वर, ईमानदारी और सही नीतियों के साथ यह काम किया जाएगा तो इस कारों को करने में कोई निर्णय नहीं है। दूसरी ओर किसानों को भी प्रयास करना चाहिए कि एक फॉम्यूल पद्धति छोड़ दें अब अन्य फसलों के सही दाम लिए जा सकें। इस हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक 5 एकड़ का किसान रबी सीजन में गेहूं की फसल से 100 विक्रील उत्पादन लेता है, जबकि खरीफ सीजन में धन लगाकर 75 विक्रील उत्पादन प्राप्त हुआ। अब किसान के पास भंडारण की अपेक्षा अधिक दाम भी मिलता, खर्च भी कम होगा और मजबूरी में बेचने की समस्या भी निजात मिलती। किसान ने हर फसल का समिति उत्पादन किया है जिसे वह बाजार और अपने हिसाब से बेच सकता है। इन फसलों के अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं जिन्हें अपने खेत में लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यदि अधिक-से-अधिक फसलें अपने खेत में उत्पादित करें तो सरकारों और व्यापारियों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो-एक डस्टले लेकर 15 एकड़ वाले छोड़ किसान वाले जाएं तो इन कारों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें। यदि अपने ग्राहकों को भरोसे की गारंटी और मर्डिंगों के बचकरों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें। यदि अपने ग्राहकों के भरोसे खेती न करें, बल्कि अपने ग्राहकों के भरोसे खेती करें। सरकार चाहे 'एमएसपी' की गारंटी न दे, परन्तु यदि अपने ग्राहकों को भरोसे की गारंटी और मर्डिंगों के बचकरों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें तो कामयाब हो गए। ताकि उत्पादन को नियोन्ट करें फसलों के सही दाम लिए जा सकें। इस हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक 5 एकड़ का किसान रबी सीजन में गेहूं की फसल से 100 विक्रील उत्पादन लेता है, जबकि खरीफ सीजन में धन लगाकर 75 विक्रील उत्पादन प्राप्त हुआ। अब किसान के पास भंडारण की अपेक्षा अधिक दाम भी मिलता, खर्च भी कम होगा और मजबूरी में बेचने की समस्या भी निजात मिलती। किसान ने हर फसल का समिति उत्पादन किया है जिसे वह बाजार और अपने हिसाब से बेच सकता है। इन फसलों के अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं जिन्हें अपने खेत में लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यदि अधिक-से-अधिक फसलें अपने खेत में उत्पादित करें तो सरकारों और व्यापारियों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो-एक डस्टले लेकर 15 एकड़ वाले छोड़ किसान वाले जाएं तो इन कारों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें। यदि अपने ग्राहकों को भरोसे की गारंटी और मर्डिंगों के बचकरों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें। यदि अपने ग्राहकों के भरोसे खेती न करें, बल्कि अपने ग्राहकों के भरोसे खेती करें। सरकार चाहे 'एमएसपी' की गारंटी न दे, परन्तु यदि अपने ग्राहकों को भरोसे की गारंटी और मर्डिंगों के बचकरों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें तो कामयाब हो गए। ताकि उत्पादन को एक्योन्ट करें फसलों के सही दाम लिए जा सकें। इस हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक 5 एकड़ का किसान रबी सीजन में गेहूं की फसल से 100 विक्रील उत्पादन लेता है, जबकि खरीफ सीजन में धन लगाकर 75 विक्रील उत्पादन प्राप्त हुआ। अब किसान के पास भंडारण की अपेक्षा अधिक दाम भी मिलता, खर्च भी कम होगा और मजबूरी में बेचने की समस्या भी निजात मिलती। किसान ने हर फसल का समिति उत्पादन किया है जिसे वह बाजार और अपने हिसाब से बेच सकता है। इन फसलों के अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं जिन्हें अपने खेत में लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यदि अधिक-से-अधिक फसलें अपने खेत में उत्पादित करें तो सरकारों और व्यापारियों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो-एक डस्टले लेकर 15 एकड़ वाले छोड़ किसान वाले जाएं तो इन कारों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें। यदि अपने ग्राहकों को भरोसे की गारंटी और मर्डिंगों के बचकरों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें। यदि अपने ग्राहकों के भरोसे खेती न करें, बल्कि अपने ग्राहकों के भरोसे खेती करें। सरकार चाहे 'एमएसपी' की गारंटी न दे, परन्तु यदि अपने ग्राहकों को भरोसे की गारंटी और मर्डिंगों के बचकरों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें तो कामयाब हो गए। ताकि उत्पादन को एक्योन्ट करें फसलों के सही दाम लिए जा सकें। इस हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक 5 एकड़ का किसान रबी सीजन में गेहूं की फसल से 100 विक्रील उत्पादन लेता है, जबकि खरीफ सीजन में धन लगाकर 75 विक्रील उत्पादन प्राप्त हुआ। अब किसान के पास भंडारण की अपेक्षा अधिक दाम भी मिलता, खर्च भी कम होगा और मजबूरी में बेचने की समस्या भी निजात मिलती। किसान ने हर फसल का समिति उत्पादन किया है जिसे वह बाजार और अपने हिसाब से बेच सकता है। इन फसलों के अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं जिन्हें अपने खेत में लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यदि अधिक-से-अधिक फसलें अपने खेत में उत्पादित करें तो सरकारों और व्यापारियों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो-एक डस्टले लेकर 15 एकड़ वाले छोड़ किसान वाले जाएं तो इन कारों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें। यदि अपने ग्राहकों को भरोसे की गारंटी और मर्डिंगों के बचकरों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें। यदि अपने ग्राहकों के भरोसे खेती न करें, बल्कि अपने ग्राहकों के भरोसे खेती करें। सरकार चाहे 'एमएसपी' की गारंटी न दे, परन्तु यदि अपने ग्राहकों को भरोसे की गारंटी और मर्डिंगों के बचकरों के बारे में भी चौका बढ़ावा दें तो कामयाब हो गए। ताकि उत्पादन को एक्योन्ट करें फसलों के सही दाम लिए जा सकें। इस हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक 5 एकड़ का किसान रबी सीजन में गेहूं की फसल से 100 विक्रील उत्पादन लेता है, जबकि खरीफ सीजन में धन लगाकर 75 विक्रील उत्पादन प्राप्त हुआ। अब किसान के पास भंडारण की अपेक्षा अधिक दाम भी मिलता, खर्च भी कम होगा और मजबूरी में बेचने की समस्या भी निजात मिलती। किसान ने हर फसल का समिति उत्पादन किया है जिसे वह बाजार और अपने हिसाब से बेच सकता है। इन फसलों के अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं जिन्हें अपने खेत में लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यदि अधिक-से-अधिक फसलें अपने खेत में उत्पादित करें तो सरकारों और व्यापारियों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो-एक डस्टले लेकर 15 एकड

